

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 11/2016

प्रार्थी-

अणदुदेवी पत्नी टीकाराम  
जाति जाट निवासी निरीया  
नाडा (पांयला कला) तह0  
सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा जरिये  
सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी  
चौसीरा तह. सिणधरी जिला बाड़मेर
2. नाथाराम पुत्र भेराराम
3. सताराम पुत्र भेराराम  
जातियान जाट निवासी सिणधरी  
चौसीरा तहसील सिणधरी जिला  
बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 301 दिनांक 02.01.2008 जो अप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री जोंगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27.08.2019

1. प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के तहत ग्राम सिणधरी चौसीरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 301 दिनांक 02.01.2008 जारी किया गया। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

पंचायत निगरानी/11/2016/अणदु देवी बनाम ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा व अन्य

1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पालना किये बिना ही जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सिणधरी चौसीरा में कई फर्जी पट्टे जारी किये थे और अन्य कई प्रकार के घोटाले व गबन किया था और बाद में सबूतों को नष्ट करने के लिये पंचायत का समस्त रेकॉर्ड जला दिया गया था। आलौच्य पट्टा सं. 301 दिनांक 02.01.2003 को जारी किया हुआ नहीं है क्योंकि यदि यह पट्टा उक्त तिथी को जारी किया होता तो उसकी प्रति सिविल न्यायालय बालोतरा में वाद सं. 20/2002 अनवान अणदु देवी बनाम नाथाराम वगैरह में अवश्य पेश करते जो दिनांक 23.04.2016 को पेश की हैं। विवादित पट्टे के नाप व पड़ोस पूर्व में जारी आबादी सर्वे रिपोर्ट, सिविल वाद की मौका कमिश्नर रिपोर्ट, पूर्व में विभिन्न मामलों में बनाई गई पुलिस थाना सिणधरी के द्वारा मौका रिपोर्ट मय नक्शा में भी मेल नहीं खाते हैं, इस आधार पर आलौच्य पट्टा विलेख खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि विवादित पट्टा अन्तर्गत आने वाली भूमि प्रार्थीनी के पति टीकाराम ने वर्ष 1989 में जरिये रजिस्ट्री खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था और रहवास हेतु दो पड़वे व पानी का टांका बनाया गया। उक्त भूमि का आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के तत्कालीन सरपंच हिमताराम सैन द्वारा जारी किया गया है जिसके खिलाफ फर्जी पट्टे जारी करने, पंचायत का



  
जिला कलक्टर  
बाडमेर

पंचायत निगरानी/11/2016/अण्डु देवी बनाम ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा व अन्य

रेकॉर्ड गायब करने का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके फलस्वरूप उसे निलम्बित किया गया। उक्त निलम्बित सरपंच द्वारा पुरानी तारीखों में पट्टे जारी किये गये हैं। आलौच्य पट्टा विलेख विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को नहीं अपनाकर, निगरानीकर्ता के कब्जे व अन्य किसी प्रकार की कोई सूचना आदि नहीं देकर फर्जी पट्टा पुरानी तारीख में जारी किया गया है जो खारिज योग्य हैं। अतः प्रार्थनी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा सं. 301 दिनांक 02.01.2008 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

4. अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 301 दिनांक 02.01.2008 पूर्णतया विधि सम्मत है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में बताये गये नियमों की पालना करते हुए जारी किया गया है। पंचायतीराज कानून में निगरानी प्रस्तुत करने की कोई मयाद निर्धारित नहीं की गई है परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई न्याय दृष्टान्तों में किसी पट्टे को निगरानी के माध्यम से चुनौती देने की मयाद 3 वर्ष निर्धारित की है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा पट्टा संख्या 301 दिनांक 02.01.2008 को जारी किया गया है, जिसकी वैधता, औचित्यता या अनियमितता के बारे में दिनांक 18.05.2016 को लगभग 8 वर्ष बाद असाधारण विलम्ब (Inordinate delay) के बाद चुनौती दी है। इस असाधारण विलम्ब को क्षमा करने हेतु निगरानीकर्ता की ओर से पृथक से कोई धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद के बिन्दु पर निरस्त योग्य है।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा यह भी प्रकट किया कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में सारे तथ्य गलत, निराधार एवं भ्रम उत्पन्न करने हेतु अभिकथित किये हैं जबकि वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में विधि अनुसार पट्टा जारी किया



  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

पंचायत निगरानी/11/2016/अणदु देवी बनाम ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा व अन्य

हैं तथा इसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 का अवासीय मकान कई वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं परन्तु इसका पट्टा नहीं होने से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पुराने गृह विनियमितीकरण करने हेतु आवेदन पत्र मय नक्शा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया तथा नियमानुसार 50 रुपये फीस जमा करवाये। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम कर वादग्रस्त स्थल का मौका देखने हेतु ग्राम पंचायत के 3 सदस्यों की कमेटी का गठन कराके मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवायी तथा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर आलौच्य पट्टा सं. 301 दिनांक 02.01.2008 को जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सारी प्रक्रिया अपनाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा जारी किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। दिनांक 09.03.2008 को ग्राम पंचायत सिणधरी भवन में विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड जल गया जिससे अप्रार्थीगण के पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है किन्तु इससे यह कयास नहीं लगाया जा सकता है कि पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा जारी करने की कोई पत्रावली कायम नहीं की है। अतः प्रार्थनी का निगरानी प्रार्थना पत्र गलत, निराधार एवं मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सूना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में आलौच्य पट्टा भिलेख जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। यह भी कथन किया है कि विवादित भूमि उसके पति द्वारा पंजिबद्ध विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है तथा इस भूमि से सम्बन्धित सिविल न्यायालय बालोतरा में विचारित वाद सं. 20/2002 में आलौच्य पट्टा दिनांक 23.04.2016 को प्रस्तुत किया है अर्थात् 02.01.2008 को जारी पट्टा



  
जिला कलक्टर  
बाडमेर

इतनी लम्बी समयावधि बाद प्रस्तुत करना जाहिर करता हैं कि यह पुरानी तारीख मे जारी करवाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नजीर 2015(4) डीएनजे (राज) पेज सं. 1853 एवं एसबी सिविल रिट संख्या 841/2019 निर्णय दिनांक 17.01.2019 की प्रतियां प्रस्तुत कर कथन किया कि पंचायतीराज नियमों के अधीन जारी पट्टों के विरुद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मयाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 3 वर्ष निर्धारित की गई हैं जबकि आलौच्य पट्टा के विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र करीब 8 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया हैं जो मयाद बाहर हैं। मयाद के बिन्दु पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्य इस आधार पर ग्राह्य नहीं हैं कि क्योंकि स्वयं अप्रार्थी ने आलौच्य पट्टा की प्रति सिविल न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे अत्यन्त ही देरी से प्रस्तुत की हैं, ऐसे मे यह स्पष्ट नहीं हो रहा हैं कि आलौच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड पर स्वामित्व व कब्जा किस पक्षकार का है, किन्तु ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा जारी किया गया पट्टा विलेख राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों का पालना करते हुए जारी किया जाना प्रतीत नहीं हो रहा है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों मे पंचायत की कार्यवाही के किसी प्रक्रम का ठोस प्रमाण प्रकट नहीं किया गया है और न ही किसी अन्य न्यायालय अथवा उप पंजियक के समक्ष उक्त पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा पंजिबद्ध कराये जाने का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है, जिसके आधार पर उसकी सत्यता एवं वैधानिकता को माना जावे। ऐसे मे ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा जारी करने मे नियमानुसार रेकॉर्ड संधारित कर कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता है तथा अनियमित रूप से मात्र पट्टा विलेख जारी किया गया है जो अवैध, अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

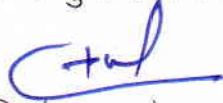


7.  
जिला कलक्टर  
बाडमेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्राथीनी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 301 दिनांक 02.01.2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जा दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(हिमाशु गुप्ता)  
जिला कलक्टर, बाडमेर  
**जिला कलक्टर**  
**बाडमेर**